अल्पसंख्यक कल्याण

94. आगामी वर्ष, मदरसों हेतु 1 हजार 500 कंप्यूटर पैराटीचर्स तथा 1 हजार 500 शिक्षा सहयोगियों की भर्ती की जायेगी। मदरसा पैराटीचर्स की विभिन्न श्रेणियों के मानदेय में 1 जुलाई 2013 से 600 से 800 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की जायेगी।

कृषि

138. सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम तकनीकों के माध्यम से किसानों को बाजार भावों की जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जयपुर में Agri-Market Intelligence and Business Promotion Centre की स्थापना करने की मैं घोषणा करता हूँ। इस केन्द्र की स्थापना से किसान, बाजार की स्थिति देखकर फसल बेचने के संबंध में निर्णय ले सकेंगे। साथ ही, यह केन्द्र उपजों एवं बाजार के संबंध में भी आवश्यक सलाहकार सेवायें उपलब्ध करवायेगा। इसके अतिरिक्त, राज्य में 2 मेगा फूडपार्क, बीकानेर एवं जोधपुर में स्थापित किये जायेंगे।

166. प्रदेश के युवाओं में तकनीकी दक्षता विकसित करने की दृष्टि से आगामी वर्ष 25 नये ITI स्थापित किये जायेंगे, जिनमें से 10 महिला ITI होंगे। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कंप्यूटर लैब्स स्थापित करने हेतु भी 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही, नये ITI की स्थापना करने हेतु निजी क्षेत्रा को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 25 लाख रुपये प्रति ITI की दर से राज्य सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी।

शिक्षा

173. **राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना** के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं एवं बारहवीं कक्षा की परीक्षा में मेरिट में प्रथम 10–10 हजार, आठवीं कक्षा की परीक्षा में विद्यालय में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित करने की

योजना आगामी वर्ष भी जारी रखी जायेगी। आगामी वर्ष इस योजना का और विस्तार करते हुए कक्षा आठवीं में विद्यालय में दूसरे से ग्यारहवाँ स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लगभग 6 हजार रुपये मूल्य के **'टेबलेट–पीसी'** उपलब्ध करवाये जायेंगे। इसके फलस्वरूप, आगामी वर्ष में, प्रदेश के लगभग 55 हजार बालक–बालिकाओं को **'लैपटॉप'** एवं लगभग 3 लाख 50 हजार बालक–बालिकाओं को **'टेबलेट–पीसी'** उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे उनको कंप्यूटर व इंटरनेट के उपयोग हेतु प्रेरित किया जा सकेगा। इस योजना के क्रियान्वयन पर लगभग 350 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

तकनीकी शिक्षा

182. विगत चार वर्षों में देश की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं, IIT, IIM, AIIMS एवं NIFT की राज्य में स्थापना की गई है। इसी क्रम में कोटा में IIIT की स्थापना हेतु सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं तथा शीघ्र ही निजी निवेशकों के साथ सहमति–पत्रा हस्ताक्षरित कर कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, आगामी वर्ष बीकानेर में एक तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करने की मैं घोषणा करता हूँ।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

194. आज के युग में ई–प्रशासन के महत्त्व से सभी परिचित हैं। इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य में **'इलेक्ट्रोनिक डिलिवरी ऑफ सर्विसेज अधिनियम'** बनाया जायेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत समस्त सूचनायें इलेक्ट्रोनिक माध्यम से निश्चित समय में उपलब्ध कराने की वैधानिक बाध्यता होगी।

195. **'आधार योजना'** की क्रियान्विति हेतु प्रत्येक तहसील व जिला मुख्यालय पर स्थाई आधार नामांकन केन्द्र प्रारंभ किये जायेंगे। इस योजना के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुँचाया जा सकता है। अतः पेंशन, छात्रावृत्ति व सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि को आधार कार्ड से जोड़ा जायेगा। इसके अतिरिक्त, आधार योजना को प्रदेश में

वर्तमान में लागू Integrated Financial Management System (IFMS) से भी जोड़ा गया है, ताकि कोषालय के माध्यम से लाभार्थियों को राशियों का हस्तांतरण किया जा सके।

गृह

247. जयपुर तथा जोधपुर शहरों में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से Integrated Traffic Management System की 30 करोड़ रुपये की लागत से स्थापना की जायेगी। इसके अतिरिक्त, जोधपुर कमिश्नरेट में 17 पुलिस थानों के लिए पीसीआर वैन्स स्वीकृत की जायेंगी।

देशी एवं विदेशी पर्यटकों, व्यवसायियों और आम नागरिकों को इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सेवायें उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मैं यह घोषणा करता हूँ कि जयपुर शहर में 50 स्थानों पर वाई–फाई हॉट स्पॉट विकसित किये जायेंगे।

विभिन्न सरकारी सूचनाओं एवं सेवाओं की पहुँच आम नागरिकों तक, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी एवं मोबाइल टेलीफोनी का एकीकरण कर विभिन्न विभागों की कम से कम एक सेवा, प्रदेशवासियों को मोबाइल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जायेगी।